प्रस्तावित डिजिटल रुपया

प्रिलिम्स के लिये:

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), ई-रुपया, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC), वर्चुअल करेंसी, डिजिटल पेमेंट।

मेन्स के लिये:

ई-रुपया और आभासी मुद्राओं का महत्त्व।

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) जल्द ही विशिष्ट उपयोग के लिये **ई-रुपए,** या **सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) या डिजिटल रुपए को** व्यापक रूप से शुरू करेगा।

- इसने खुदरा और थोक के रूप में विभिन्न लेन-देन के लिये ई-रुपए के उपयोग की दो व्यापक श्रेणियों का संकेत दिया है।

ई-रुपया

- **परिभाषा**: RBI, CBDC को **केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किये गए मुद्रा के डिजिटल संस्करण के रूप में परिभाषित करता है।** देश की मौद्रिक नीति के अनुसार यह केंद्रीय बैंक (इस मामले में, आरबीआई) द्वारा जारी एक संप्रभु या पूरी तरह से स्वतंत्र मुद्रा है।
- **लीगल टेंडर**: एक बार आधिकारिक रूप से जारी होने के बाद**CBDC को तीनों पक्षों - नागरिक, सरकारी निकायों और उद्यमों द्वारा भुगतान का माध्यम एवं लीगल टेंडर माना जाएगा।** सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होने के कारण इसे किसी भी वाणिज्यिक बैंक की मुद्रा या नोटों में स्वतंत्र रूप से परिवर्तित किया जा सकता है।
    - RBI **ई-रुपए पर ब्याज के पक्ष में नहीं है** क्योंकि लोग बैंकों से पैसे निकालकर इसे डिजिटल रुपए में बदल सकते हैं, जिससे बैंक विफल हो सकते हैं।
- **क्रिप्टोकरेंसी से भिन्नता: क्रिप्टोकरेंसी (डिस्ट्रिब्यूटेड लेज़र)** की अंतर्निहित तकनीक डिजिटल रुपया प्रणाली के कुछ आयामों को कम कर सकती है, लेकिन आरबीआई ने अभी तक इस पर फैसला नहीं किया है। हालाँकि**बिटकॉइन या एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी प्रकृति में 'निजी' हैं। दूसरी ओर, डिजिटल रुपए को आरबीआई द्वारा जारी और नियंत्रित किया जाएगा।**
- **वैश्विक परिदृश्य:** जुलाई 2022 तक करीब 105 देश CBDC पर विचार कर रहे थे। **दस देशों ने CBDC की शुरुआत कर दी है** जिनमें सबसे पहला है वर्ष 2020 में **बहामियन सैंड डॉलर तथा सबसे नवीनतम है जमैका का JAM-DEX**।

CBDC के लिये RBI की योजना:

- **CBDC के प्रकार**: **डिजिटल रुपए के उपयोग और कार्यों के आधार तथा उसकी पहुँच के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए CBDC को दो व्यापक श्रेणियों** में बाँटा जा सकता है- **सामान्य उद्देश्य वाला (खुदरा) (CBDC-R)** और **थोक (CBDC-W)**।
    - **खुदरा CBDC नकदी का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है जो मुख्य रूप से खुदरा लेन-देन हेतु है।** इसका उपयोग सभी द्वारा किया जाएगा यथा-निजी क्षेत्र, गैर-वित्तीय उपभोक्ता और व्यवसाय। हालाँकि**RBI ने यह नहीं बताया है कि खुदरा व्यापार में मर्चेंट ट्रांजैक्शंस में ई-रुपए का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है**।
    - **थोक CBDC को चुनिंदा वित्तीय संस्थानों तक सीमित पहुँच के लिये** डिज़ाइन किया गया है। इसमें बैंकों द्वारा किये गए वित्तीय लेन-देन के लिये निपटान प्रणालियों को सरकारी प्रतिभूतियों (ज) सेगमेंट, अंतर-बैंक बाज़ार और पूंजी बाज़ार में परिचालन लागत, संपार्श्विक के उपयोग एवं तरलता प्रबंधन के संदर्भ में अधिक कुशलतापूर्वक तथा सुरक्षित रूप से बदलने की क्षमता है।
- **ढाँचा:**
    - **टोकन पर आधारित CBDC बैंक नोटों के समान लेन-देन एक साधन होगा;** टोकन प्राप्त करने वाले को टोकन के अपने स्वामित्व की वैधता को प्रमाणित करना होगा। चूँकि यह वास्तविक धन के समान होगा, टोकन-आधारित CBDC को पसंदीदा CBDC-खुदरा मोड के रूप में देखा जाएगा।

- किसी भी **खाता-आधारित प्रणाली** के लिये CBDC के **सभी धारकों के शेष और लेन-देन के रिकॉर्ड के रखरखाव की आवश्यकता होगी तथा मौद्रिक शेष राशि के स्वामित्व को इंगित करना होगा** । इस संदर्भ में एक मध्यस्थ एक खाताधारक की पहचान को सत्यापित करेगा। CBDC-थोक हेतु इस प्रणाली पर विचार किया जा सकता है।
- **ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में उपलब्ध:** एक विकल्प के रूप में ऑफलाइन कार्यक्षमता CBDC को इंटरनेट के बिना लेन-देन करने की अनुमति देगी और इस प्रकार **खराब या बिना इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों में पहुँच को सक्षम करेगी।**
  - यह **वित्तीय प्रणाली से असंबद्ध आबादी के लिये डिजिटल पदचिह्न साबित होगा** , जिससे उन्हें ऋण की आसान उपलब्धता की सुविधा प्राप्त होगी।
  - हालाँकि RBI को लगता है कि ऑफलाइन मोड में **'दोहरे खर्च'** का जोखिम रहेगा क्योंकि CBDC के सामान्य खाता बही को अपडेट किये बिना **CBDC इकाई का एक से अधिक बार उपयोग करना तकनीकी रूप से संभव होगा।**
- **जारी करने के लिये मॉडल:**
  - प्रत्यक्ष मॉडल में **केंद्रीय बैंक डिजिटल रुपया प्रणाली** के सभी पहलुओं जैसे **जारी करने, खाता रखने और लेन-देन सत्यापन के प्रबंधन के लिये ज़िम्मेदार होगा।**
  - **अप्रत्यक्ष मॉडल वह होगा जहाँ केंद्रीय बैंक और अन्य मध्यस्थ (बैंक तथा कोई अन्य सेवा प्रदाता), सभी अपनी-अपनी भूमिका निभाते हैं।** केंद्रीय बैंक अप्रत्यक्ष रूप से बिचौलियों के माध्यम से उपभोक्ताओं को CBDC जारी करेगा और उपभोक्ताओं के किसी भी दावे का प्रबंधन मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा।

ई-रुपए के फायदे:

- भौतिक नकद प्रबंधन में शामिल **परिचालन लागत में कमी, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना, भुगतान प्रणाली में लचीलापन, दक्षता और नवीनता लाना।**
- जनता को ऐसी सुविधा प्रदान करता है जो कोई भी निजी आभासी मुद्राएँ संबद्ध जोखिमों के बिना प्रदान कर सकती हैं।

भारत में CBDC से संबंधित मुद्दे:

- **साइबर सुरक्षा:** CBDC पारिस्थितिकी तंत्र को **साइबर हमलों जैसे जोखिम हो सकते हैं जो वर्तमान भुगतान प्रणाली में पहले से मौजूद हैं।**
- **गोपनीयता का मुद्दा:** CBDC से वास्तविक समय में डेटा के विशाल मात्रा के उत्पन्न होने की उम्मीद है। डेटा की गोपनीयता इसकी अनामकिता से संबंधित चिंताएँ और इसका प्रभावी उपयोग एक चुनौती होगी।
- **डिजिटल अंतराल और वित्तीय निरक्षरता:** राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (National Family Health Survey-NFHS)-5 ग्रामीण-शहरी विभाजन के आधार पर डेटा पृथक्करण की सुविधा भी प्रदान करता है। केवल 48.7% ग्रामीण पुरुषों और 24.6% ग्रामीण महिलाओं ने कभी इंटरनेट का उपयोग किया है। इसलिये CBDC डिजिटल डिवाइड के साथ-साथ वित्तीय समावेशन में लिंग आधारित बाधाओं को बढ़ा सकता है।

आगे की राह

- उन **अंतर्निहित तकनीकों पर निर्णय** लेने के लिये तकनीकी स्पष्टता सुनिश्चित की जानी चाहिये जिन पर **सुरक्षा और स्थिरता** के लिये भरोसा किया जा सकता है।
- CBDC को एक सफल पहल और आंदोलन बनाने के लिये **RBI को व्यापक आधार हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी स्वीकृति बढ़ाने के लिये मांग पक्ष के बुनियादी ढाँचे तथा** ज्ञान के अंतराल को दूर करना चाहिये।
- **RBI को विभिन्न मुद्दों, डिज़ाइन के विचारों और डिजिटल मुद्रा** की शुरुआत के निकट प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सावधानी से आगे बढ़ना चाहिये।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/proposed-digital-rupee